

अध्याय-॥

**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों
(विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का
वित्तीय प्रदर्शन**

अध्याय-II

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन

2.1 परिचय

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) थे। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 19 सरकारी कंपनियों, दो²⁵ सांविधिक निगम एवं सरकार के नियंत्रणाधीन चार²⁶ अन्य कंपनियों सम्मिलित हैं। 19 सरकारी कंपनियों में से दो कंपनियों²⁷ एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियों में से एक कंपनी²⁸ अकार्यशील हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के दो नए उद्यमों²⁹ का गठन किया गया था।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन एवं इनकी प्रकृति तालिका-2.1 में दर्शाई गई हैं।

तालिका-2.1: इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रकृति एवं कवरेज

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रकृति	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कुल संख्या	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कुल संख्या				कुल	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिनके प्रथम लेखें प्राप्त नहीं हुए अथवा परिसमापनाधीन हैं
		लेखे					
		2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 तक एवं विगत वर्षों के लेखे		
सरकारी कंपनियां	19	6	3	2	5	16	3 ³⁰
सांविधिक निगम	2	1	1	0	0	2	0
कुल	21	7	4	2	5	18	3
सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	4	2	0	1	0	3	1 ³¹
सकल योग	25	9	4	3	5	21	4

नियंत्रक-लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आने वाली सभी सरकारी कंपनियों/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं संविधानिक निगमों के नाम, साथ ही निगमन का माह व वर्ष, प्रशासन विभाग तथा उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

²⁵ हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश विक्त निगम।

²⁶ धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑरगनाइजेशन लिमिटेड। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (अकार्यशील कंपनी)।

²⁷ एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड।

²⁸ हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।

²⁹ श्री नैनादेवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड व रोपवे एंड रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड।

³⁰ श्री नैनादेवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड व रोपवे एंड रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

³¹ हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (अकार्यशील कंपनी)।

इस प्रतिवेदन में 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम लेखाओं के आधार पर उनके परिणाम सम्मिलित किये गए हैं।

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इन विभागों (क्षेत्रों) के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति का विभाजन एवं विश्लेषण किया गया है।

31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) के वित्तीय निष्पादन का सारांश

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	25
सम्मिलित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	25
प्रदत्त पूंजी (राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹1,090.67 करोड़
हिमाचल प्रदेश सरकार का इक्विटी निवेश (राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹1,056.24 करोड़
दीर्घावधि ऋण (राज्य के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹431.63 करोड़
समेकित लाभ/हानि (राज्य के 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	(-) ₹154.41 करोड़
निवल लाभ (राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹42.07 करोड़
निवल हानि (राज्य के 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	(-) ₹196.48 करोड़
राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई या जिन्होंने अब तक उनके प्रथम लेखे / लाभ व हानि के लेखे नहीं बनाए	छः
लाभांश का भुगतान/ घोषित किया गया (राज्य के 03 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹2.25 करोड़
राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश घोषित नहीं किया (राज्य के 04 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹1.34 करोड़
कुल परिसंपत्तियां	₹3,629.19 करोड़
टर्नओवर	₹3,290.26 करोड़
नेटवर्थ	(-) ₹636.18 करोड़
संचित हानि	₹1,726.85 करोड़

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार

सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर तथा हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण नीचे तालिका-2.2 में दिया गया है।

तालिका-2.2: हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का विवरण

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का टर्नओवर	2,471.95	2,743.10	2,821.02	3,400.40	3,290.26
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (चालू मूल्यों पर)	1,14,239	1,25,634	1,38,351	1,53,845	1,65,472
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर की प्रतिशतता	2.16	2.18	2.04	2.21	1.99

(₹ करोड़ में)

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर संकलित।

राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का टर्नओवर 2015-16 से 2018-19 तक स्थिर रहा परन्तु 2018-19 में रुपए 3,400.40 करोड़ से थोड़ा घटकर 2019-20 में ₹3,290.26 करोड़ हो गया। 2015-19 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि 2.84 प्रतिशत से 20.54 प्रतिशत के मध्य रही, परन्तु विगत वर्ष अर्थात् 2018-19 की अपेक्षा 2019-20 में 3.24 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई। 2015-20 की अवधि के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7.56 प्रतिशत से 11.20 प्रतिशत के मध्य रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि-दर विभिन्न समयावधियों में विकास दर मापने की एक उपयोगी पद्धति होती है। हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विगत पांच वर्षों में 9.71 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 9.71 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर के प्रति राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) ने विगत 5 वर्षों के दौरान 7.41 प्रतिशत की कम का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर दर्ज की। इसके परिणामस्वरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के टर्नओवर का अंश 2015-16 के 2.16 प्रतिशत से 2019-20 में 1.99 प्रतिशत घट गया।

2.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को संचालित करने वाले विभागों के आधार पर किये गए महत्वपूर्ण वर्गीकरण के तहत उनकी स्थिति का विभाजन एवं विश्लेषण किया गया है। राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य सरकार ने राज्य के केवल 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश किया एवं राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों³² में कोई राशि निवेशित नहीं की गई। 31 मार्च 2020 की समाप्ति तक राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी एवं ऋण में निवेश की गई राशि के विवरण परिशिष्ट-III में तथा तालिका-2.3 में दिया गया है।

³² हिमाचल कंसल्टेंसी ऑरगनाइजेशन लिमिटेड व हिमाचल वस्टेड मिल्स लिमिटेड।

तालिका-2.3: राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश तथा ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश का स्रोत	31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
केंद्र सरकार	19.03	29.77	20.57	19.03	1.54	20.57
राज्य सरकार	1,064.64	209.22	1,273.86	1,145.89	220.33	1,366.22
केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियां	6.18	0	6.18	6.18	63.57	69.75
अन्य	8.67	138.67	147.34	9.22	151.13	160.35
योग	1,098.52	377.66	1,476.18	1,180.32	436.57	1,616.89
राज्य सरकार का सकल इक्विटी/ऋण में अंश (प्रतिशत में)	96.92	55.40	88.11	97.08	50.47	84.50

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश (इक्विटी व दीर्घावधि ऋण) ₹1,616.89 करोड़ था, जिसने 31 मार्च 2019 से ₹140.71 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में उल्लेखनीय इक्विटी निवेश (₹79.39 करोड़) किया।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋण का 50.47 प्रतिशत (₹220.33 करोड़) था एवं 31 मार्च 2019 की अपेक्षा ₹11.11 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के सन्दर्भ में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, ऋण को बढ़े-खाते में डालना एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण के रूप में बजटीय बहिर्गमन (बजटरी आउटगो) का संक्षिप्त विवरण तालिका-2.4 में नीचे दिया गया है:

तालिका-2.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण ³³	2017-18		2018-19		2019-20	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी	2	50.80	3	62.85	4	81.25
दिए गए ऋण	1	5.44	1	4.10	1	3.90
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	6	423.63	9	416.36	8	671.15
कुल बहिर्गमन		479.87		483.31		756.30
बट्टे-खाते में डाला गया ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी गारंटी	5	192.65	5	115.60	5	108.60
गारंटी प्रतिबद्धता/बकाया	5	277.98	1	0.60	6	196.24

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

2.2.1 इक्विटी में निवेश

2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में इक्विटी के अंकित मूल्य पर कुल निवेश में ₹81.25 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार द्वारा किया गया इक्विटी में निवेश चार्ट-2.1 में दर्शाया गया है।

³³ राशि केवल राज्य के बजट से बहिर्गमन को दर्शाती है।

चार्ट-2.1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में इक्विटी के रूप में निवेश



■ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश ■ अन्य द्वारा इक्विटी निवेश

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित 31 मार्च 2020 तक कुल इक्विटी में 2017-18 की तुलना में ₹145.25 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा ₹144.51 करोड़) की वृद्धि हुई जो 31 मार्च 2018 से 14.03 प्रतिशत अधिक थी। यद्यपि 2018-20 के दौरान अन्य द्वारा इक्विटी निवेश लगभग स्थिर रहा।

31 मार्च 2020 तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त-पूंजी में राज्य सरकार द्वारा इक्विटी पूंजी (₹25 करोड़ से अधिक का निवेश) में किये गए महत्वपूर्ण निवेश का विवरण तालिका-2.5 में दिया गया है।

तालिका-2.5: राज्य सरकार द्वारा किये गए महत्वपूर्ण निवेश

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	(₹ करोड़ में)
		राशि
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	बागवानी	31.20
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	उद्योग	92.98
हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	25.00
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	30.82
हिमाचल पथ परिवहन निगम	यातायात	842.10

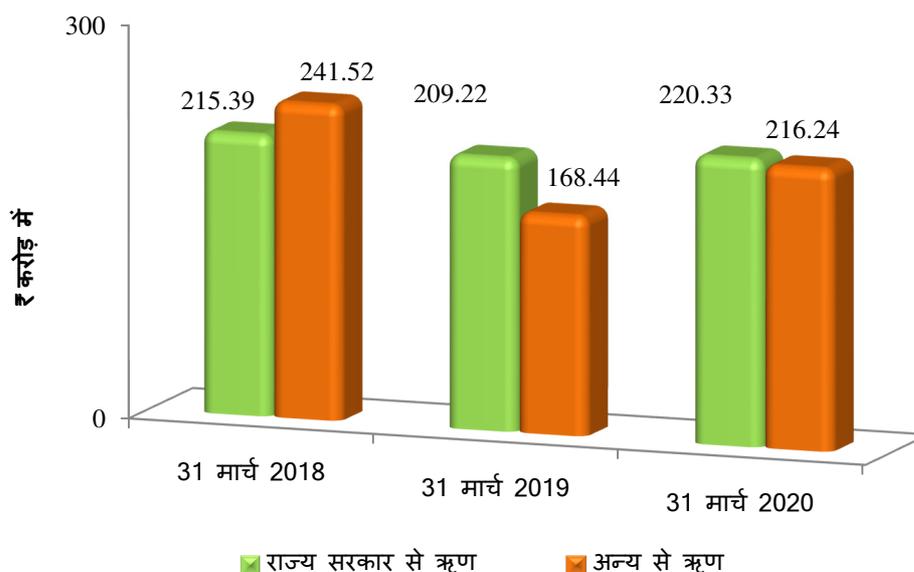
2.2.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ऋण

2.2.2.1 31 मार्च 2020 तक बकाया दीर्घावधि ऋण की गणना

31 मार्च 2020 तक के राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में सभी स्रोतों के बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹436.57 करोड़ था।

31 मार्च 2018 की तुलना में, 31 मार्च 2020 तक राज्य के इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के दीर्घावधि ऋण में ₹20.34 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में बकाया दीर्घावधि ऋण का वर्ष-वार विवरण चार्ट-2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: 31 मार्च 2020 को समाप्त विगत तीन वर्षों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का बकाया दीर्घावधि ऋण



स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से प्राप्त जानकारी के आधार पर

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋणों का 50.47 प्रतिशत (₹220.33 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 49.53 प्रतिशत (₹216.24 करोड़) भारत सरकार, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य से प्राप्त किए गए थे।

2.2.2.2 ऋण देयताओं को पूरा करने हेतु परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों से कुल कर्ज/ऋणों का अनुपात यह निर्धारित की विधियों में से एक हैं की क्या कंपनी ऋण चुकाने में समर्थ है (सॉल्वेंट) अथवा नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार बकाया ऋणों वाले राज्य के दस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल परिसंपत्ति मूल्य से दीर्घावधि ऋण का कवरेज अनुपात तालिका-2.6 में दिया गया है।

तालिका-2.6: कुल परिसंपत्तियों से दीर्घावधि ऋणों का कवरेज

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	धनात्मक कवरेज			
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	परिसंपत्तियां	दीर्घावधि ऋण	परिसंपत्ति-ऋण अनुपात
	(₹ करोड़ में)			
सांविधिक निगम	2	1,173.62	236.49	4.96:1
सरकारी कंपनियां	8	566.17	195.14	2.90:1
योग	10	1,739.79	431.63	4.03:1

स्रोत: 31 दिसम्बर 2020 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वार्षिक वित्तीय विवरणियों के आधार पर संकलित।

राज्य के दस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक अकार्यशील उद्यम (एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड) में संपत्ति ऋण अनुपात एक से कम था (0.02:1), क्योंकि कुल संपत्ति मूल्य (₹1.33 करोड़) बकाया ऋण (₹60.15 करोड़) से कम था। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का परिसंपत्ति-ऋण अनुपात सर्वोच्च होने का (206.10:1) मुख्य कारण कम ऋण राशि होना था।

2.2.2.3 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना ब्याज एवं कर चुकाने से पूर्व कंपनी के अर्जित लाभांश को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा कंपनी की ऋण का ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम पर होगी। ब्याज कवरेज अनुपात का एक से नीचे होना दर्शाता है, कि कंपनी अपने ब्याज के खर्च का पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जन नहीं कर रही है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे तालिका-2.7 साथ में दिया गया है।

तालिका-2.7: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज व कर पूर्व अर्जन (₹ करोड़ में)	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	एक के बराबर या अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या
सांविधिक निगम					
2017-18	29.86	(-) 100.77	2	0	2
2018-19	33.66	(-) 124.07	2	0	2
2019-20	27.52	(-) 132.78	2	0	2
सरकारी कंपनियां					
2017-18	5.19	13.23	10	8	2 ³⁴
2018-19	7.04	4.96	10	8	2 ³⁵
2019-20	7.90	(-)9.96	10	7	3 ³⁶

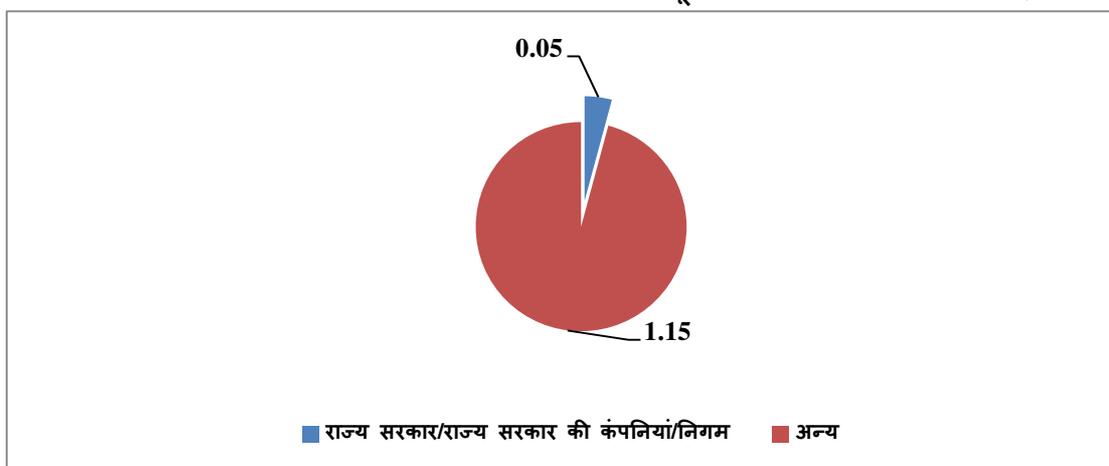
स्रोत: 31 दिसम्बर 2020 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित

राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड) का समीक्षा के तीनों वर्षों में ब्याज व कर पूर्व अर्जित लाभांश उनकी ब्याज देयताओं से कम था।

2.2.2.4 सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों में निवेश

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार³⁷ कंपनियों पूंजी निवेश चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों में पूंजीगत अंश का संघटन (₹ करोड़ में)



स्रोत: 31 दिसम्बर 2020 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित

³⁴ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड।

³⁵ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास लिमिटेड।

³⁶ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड तथा हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड।

³⁷ शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड व हिमाचल वस्टेड मिल्स लिमिटेड।

2.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल, वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है, जिसका मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात्- कर के बाद का निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। यह प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा इसकी गणना किसी भी उस कंपनी के लिए की जा सकती है, जिसकी निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि दोनों संख्या धनात्मक हो।

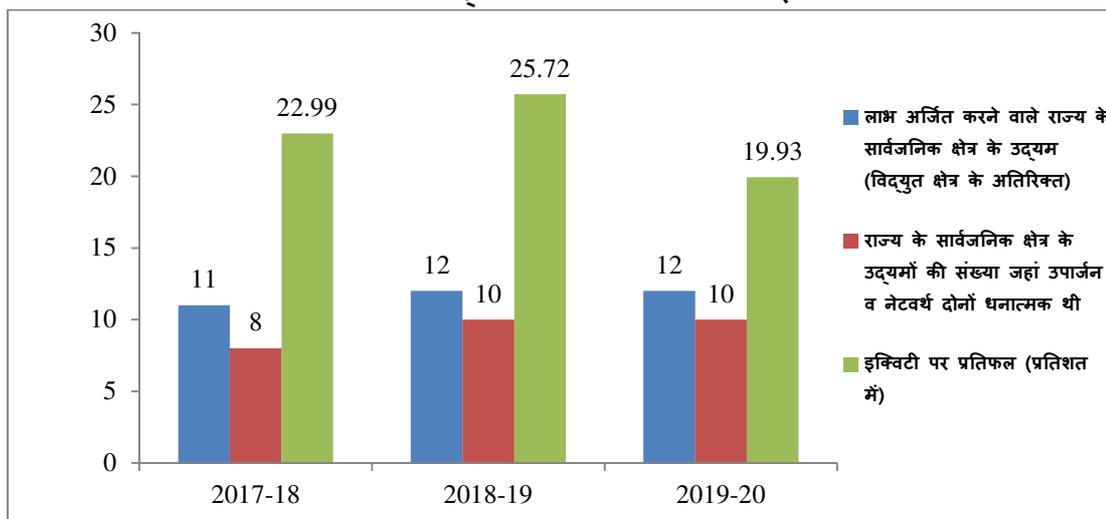
किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि अथवा नेट वर्थ की गणना प्रदत्त पूंजी व मुक्त आरक्षित निधियों, निवल संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह उजागर करती है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेच दी जाये एवं सभी ऋण चुका दिए जाए तब कंपनी के शेयरधारकों कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कंपनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

31 दिसंबर 2020 तक कंपनियों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित (₹42.07 करोड़) करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या 25 में से 12 थीं तथा राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ₹196.48 करोड़ की हानि हुई थीं जैसा कि चार्ट-2.4 में दर्शाया गया है। राज्य के छः³⁸ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने या तो उनके प्रथम लेखे/लाभ व हानि लेखा नहीं बनाया था अथवा उनके आय से अधिक व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थीं।

³⁸ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने उनके प्रथम लेखे नहीं भेजे: i) शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ii) श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड एवं iii) रोपवे व रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनका व्यय आधिक्य राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति किया गया: i) धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ii) शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड एवं iii) हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड।

चार्ट 2.4: 31 मार्च 2020 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या तथा उनकी इक्विटी पर प्रतिफल



स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

31 दिसम्बर 2020 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार दो सरकारी कंपनियां, जिन्होंने सर्वाधिक लाभ का योगदान दिया, तालिका-2.8 में सारांशित की गई हैं।

तालिका 2.8: 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभ का योगदान देने वाली दो सरकारी कंपनियां

क्र.सं.	राज्य के लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल लाभ से लाभ का प्रतिशत (₹42.07 करोड़) जिन्होंने नवीनतम अंतिम रूप लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया (राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	13.90	33.04
2	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	6.97	16.57
	योग	20.87	49.61

स्रोत: 31 दिसंबर 2020 तक राज के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वार्षिक वित्तीय विवरणियों के आधार पर संकलित

सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियों में, हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड में उसके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हानि हुई, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वर्ष 2016-17 हेतु उसकी प्रथम वित्तीय विवरणी लाभ व हानि लेखाओं के बिना तैयार की, हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से अकार्यशील थी एवं शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के संबंध में आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई।

2.3.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

राज्य सरकार ने नीति बनाई थी (अप्रैल 2011) कि लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (कल्याण एवं जनउपयोगी क्षेत्र को छोड़कर) राज्य सरकार द्वारा दी गई (अंशदत्त) प्रदत्त पूंजी के अंश पर न्यूनतम 5 प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान, कर के पश्चात 50 प्रतिशत लाभ की सीमा तक पर करेंगे। 31 दिसंबर 2020 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार, राज्य के कार्यशील 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) ने ₹32.58 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया (अकार्यशील राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-हिमाचल प्रदेश बेवेरेज लिमिटेड को छोड़ कर) जिसमें से राज्य के केवल सात³⁹ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश घोषित करने हेतु योग्य थे, यद्यपि राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹2.25 करोड़ के लाभांश की घोषणा की/भुगतान किया तथा राज्य के शेष चार लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹1.34 करोड़ के लाभांश का भुगतान/प्रदान नहीं किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभ अर्जित करने तथा लाभांश घोषित करने/भुगतान करने तथा भुगतान न करने का विवरण तालिका-2.9 में दिया गया है।

तालिका-2.9: 31 दिसंबर 2020 तक अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा घोषित अर्जित लाभ व लाभांश

श्रेणी	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राज्य के लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	लाभांश घोषित करने योग्य राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	कर व ब्याज के पश्चात् निवल लाभ	लाभांश घोषित /भुगतान करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	लाभांश घोषित /भुगतान करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	नीति के अनुसार घोषित न किया गया लाभांश
				(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	25	11	7	85.61	28.28	3	2.25	4	1.34
योग	25	11	7	85.61	28.28	3	2.25	4	1.34

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने राज्य सरकार को ₹3.51 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर 10 प्रतिशत की दर से लाभांश घोषित/ भुगतान किया (₹0.35 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने प्रदत्त पूंजी पर 5 प्रतिशत की दर से क्रमशः ₹1.54 करोड़ व ₹0.36 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। 31 दिसंबर 2020 तक राज्य के चार सार्वजनिक

³⁹ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।

क्षेत्र के उद्यमों⁴⁰ ने उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹1.34 करोड़ के लाभांश का राज्य सरकार को घोषित/भुगतान नहीं किए।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार निदेशक बोर्ड में उसके नामांकित व्यक्तियों के माध्यम से लाभांश का भुगतान न करने के मामले को उठाए।

2.3.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी पर क्षेत्र-वार प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल⁴¹ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है, जिसका मूल्यांकन शेयरधारकों की इक्विटी से निवल आय को विभाजित करके किया जाता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का क्षेत्र-वार इक्विटी पर प्रतिफल तालिका-2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.10: क्षेत्र-वार इक्विटी पर प्रतिफल

क्र.सं.	क्षेत्र	2017-18 के दौरान इक्विटी पर प्रतिफल	2018-19 के दौरान इक्विटी पर प्रतिफल	2019-20 के दौरान इक्विटी पर प्रतिफल
1	कृषि	(-) 3.04	(-) 6.77	(-) 17.43
2	वित्त	(-) 10.56	(-) 15.31	(-) 11.88
3	अवसंरचना	17.52	18.66	13.07
4	विनिर्माण	43.60	32.42	19.67
5	सेवा	(-) 21.64	(-) 20.87	(-) 24.87

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित

2.4 राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विवरण तालिका-2.11 में दिया गया है।

⁴⁰ हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड।

⁴¹ इक्विटी पर प्रतिफल = (कर एवं ग्राह्य लाभांश के पश्चात् निवल लाभ / इक्विटी) * 100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका-2.11: 30 सितम्बर 2018 व 2019 तथा 31 दिसंबर 2020 तक विगत तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या

वर्ष	हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष की निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ ⁴²
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम (क)				
2017-18	2	100.77	1,280.47	(-) 510.41
2018-19	2	124.07	1,399.04	(-) 578.98
2019-20	2	160.30	1,553.84	(-) 674.78
सरकारी कंपनियां /सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां (ख)				
2017-18	5	5.66	217.25	(-) 148.12
2018-19	5	14.38	231.72	(-) 162.42
2019-20	5	36.18	267.85	(-) 198.55
योग (क+ख)				
2017-18	7	106.43	1,497.72	(-) 658.53
2018-19	7	138.45	1,630.76	(-) 741.40
2019-20	7	196.48	1,821.69	(-) 873.33

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित

वर्ष 2019-20 में राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हुई ₹196.48 करोड़ की कुल हानि में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹154.80 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, ₹34.43 करोड़ की हानि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कारण हुई।

2.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

नेटवर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष। दरअसल यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेटवर्थ दर्शाता है कि मालिकों का संपूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजीगत निवेश एवं संचित घाटा क्रमशः ₹1,090.67 करोड़ एवं ₹1,726.85 करोड़ थे, जो ₹636.18 करोड़ के ऋणात्मक नेटवर्थ में परिणत हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-1 में वर्णित है।

अनुवर्ती तालिका-2.12, 2017-20 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) में प्रत्यक्ष निवेश किया गया, उनकी कुल प्रदत्त पूंजी, कुल संचित हानियां एवं नेटवर्थ को दर्शाती है।

⁴² नेटवर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी अंश एवं मुक्त भंडार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष, मुक्त भंडार से अर्थ है वे सभी आरक्षित निधियां जो लाभ से व प्रीमियम अंश खाते से सृजित की गई।

तालिका-2.12: 2017-20 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार उनका नेटवर्थ

वर्ष	वर्ष के अंत पर प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत पर संचित हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	नेटवर्थ
2017-18	976.46	(-) 1,445.90	-	(-) 469.43
2018-19	1,038.41	(-) 1,553.07	-	(-) 514.66
2019-20	1,090.67	(-) 1,726.85	-	(-) 636.18

(₹ करोड़ में)

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार जानकारी

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 31 दिसम्बर 2020 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹1,876.11 करोड़ थीं। राज्य के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से पांच में 31 दिसंबर 2020 तक उनके अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹195.99 करोड़ की हानि हुई तथा राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कोई हानि नहीं हुई, यद्यपि उनकी संचित हानियां ₹53.38 करोड़ थीं। राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से छः या तो नव निगमित (तीन) थे अथवा उनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई (तीन)।

राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से आठ का नेटवर्थ संचित हानियों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार राज्य के इन आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ, ₹969.73 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹890.32 करोड़ था तथा बकाया सरकारी ऋण ₹389.13 करोड़ था। इनमें से राज्य के दो⁴³ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹1.48 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

राज्य के 25 में से दो⁴⁴ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से भी कम था जो उनकी संभावित वित्तीय कमजोरी का परिचायक हैं।

2.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संचालन दक्षता

2.5.1 टर्नओवर, सम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी

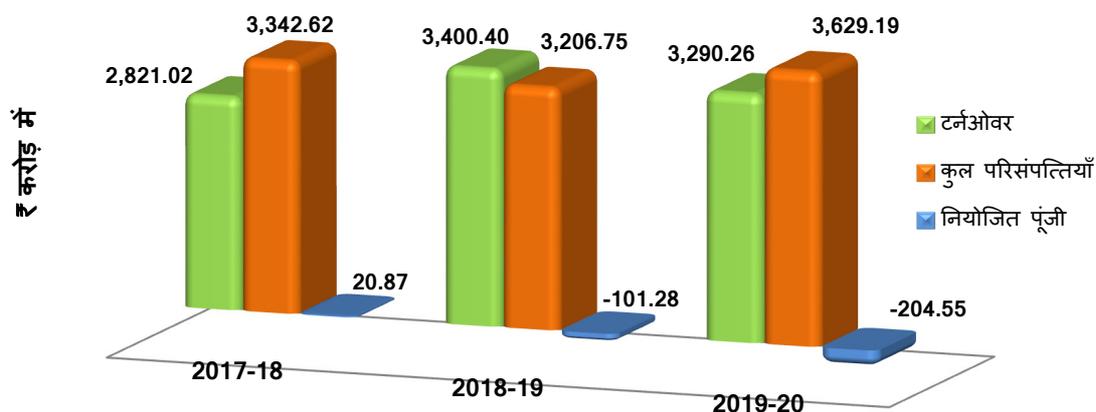
तीन साल⁴⁵ की अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का टर्नओवर, कुल परिसंपत्तियां तथा नियोजित पूंजी को दर्शाने वाला सारांश चार्ट-2.5 प्रदर्शित है।

⁴³ हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम।

⁴⁴ हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।

⁴⁵ 31 दिसंबर 2020 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार।

चार्ट 2.5: टर्नओवर, परिसम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी



स्रोत: 31 दिसम्बर 2020 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए लेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

2017-18 से 2019-20 में टर्नओवर में मामूली वृद्धि पाई गई। विगत तीन वर्षों के दौरान, कुल परिसंपत्तियाँ में ₹3,342.62 करोड़ (2017-18) से ₹3,629.19 करोड़ (2019-20) वृद्धि हुई, जैसा की परिशिष्ट-1 में वर्णित है तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वर्ष-दर वर्ष समेकित निवल हानियों के कारण नियोजित पूंजी में गिरावट हुई।

2.5.2 विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक ऐसा अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता तथा उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना, ब्याज व करों के पूर्व कंपनी के अर्जित लाभांश को नियोजित पूंजी⁴⁶ से विभाजित करके की जाती है। 2017-18 से 2019-20 अवधि के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल का विवरण तालिका-2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व कर के पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
	(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत)
2017-18	(-) 69.77	20.87	(-) 334.31
2018-19	(-) 84.69	(-) 101.28	लागू नहीं
2019-20	(-) 103.11	(-) 204.55	लागू नहीं

स्रोत: नवीनतम अन्तिमिकृत लेखाओं के अनुसार जानकारी।

⁴⁶ नियोजित पूंजी=प्रदत्त पूंजी का अंश+मुक्त भंडार व अधिशेष +दीर्घावधि ऋण -संचित हानियाँ-आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्षों के अनुसार हैं जिनके लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल प्राथमिक रूप से ऋणात्मक था, क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के संचित घाटे में क्रमशः ₹154.80 करोड़ व ₹34.43 करोड़ की वृद्धि हुई।

2.5.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश कंसल्टेंसी ऑरगनाइजेशन लिमिटेड एवं हिमाचल वस्टेड मिल्स लिमिटेड को छोड़कर) में किए गए महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक प्रतिफल की दर महत्वपूर्ण है। निवेश की केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणनाएं धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा कर देती हैं। इसलिए, इसके अतिरिक्त, वास्तविक प्रतिफल की दर की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है।

निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर चक्रवृद्धि किया जाता है तथा ब्याज की यह वर्ष-वार औसत दर सम्बंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत पर ली जाती हैं। अतः 31 मार्च 2020 तक इन कंपनियों के संचालन एवं प्रशासनिक व्यय की पूर्ति करने हेतु इक्विटी, ब्याज रहित ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा किये गए निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई।

31 मार्च 2020 तक, ऐतिहासिक मूल्य को प्रत्येक वर्ष के अंत पर उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विगत निवेश/वर्ष-वार निधियों के निवेश की गणना निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर की गई:

- जहां राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ब्याज रहित ऋण दिए गए थे एवं बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिए गए थे, वहां इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से काट कर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया।
- सम्बंधित वित्तीय वर्ष⁴⁷ के लिए सरकारी उधार ब्याज की औसत दर को वर्तमान

⁴⁷ सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन (हिमाचल प्रदेश सरकार) से अपनाया गया है जिसमें चुकाए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान / (गत वर्ष की राजकोषीय देयता की राशि - चालू वर्ष की राजकोषीय देयता की राशि) * 100।

मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए सरकार द्वारा किए गए लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।

- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटा दिया गया है।

2.5.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2020 तक इक्विटी एवं ऋण के रूप में राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश की कंपनी-वार स्थिति परिशिष्ट-2.1 में दर्शाई गई हैं। यद्यपि, इस अवधि के दौरान कोई ब्याज रहित ऋण अथवा राज्य सरकार द्वारा किये गए विनिवेश इक्विटी/अनुदान/सब्सिडी में परिवर्तित नहीं हुए।

वर्ष 1999-2000 से 2019-20 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका-2.14 में इंगित की गई है।

तालिका-2.14: राज्य सरकार द्वारा किये गए निवेश का वर्ष-वार विवरण एवं 1999-2000 से 2019-20 की अवधि हेतु सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक प्रतिफल)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/सब्सिडी	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष हेतु निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ
							ज = ग + घ - ङ + च - छ	झ = ख + ज		ट = झ * (1 + ञ / 100)	ठ = झ * ढ / 100		ढ = ड / ट * 100
1999-2000 तक	-	300.04	0.49	-	-	-	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	-	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	-	-	-	33.99	361.06	10.15	397.71	36.65	-49.50	-
2001-02	397.71	13.01	-	-	-	-	13.01	410.72	11.06	456.15	45.43	-36.70	-
2002-03	456.15	12.43	-	-	-	-	12.43	468.58	10.37	517.17	48.59	-29.19	-
2003-04	517.17	28.60	-	-	-	-	28.60	545.77	10.98	605.70	59.93	-31.10	-
2004-05	605.70	16.06	-	-	-	-	16.06	621.76	10.60	687.66	65.91	-43.44	-
2005-06	687.66	13.59	0.15	-	-	-	13.74	701.40	9.20	765.93	64.53	-30.72	-
2006-07	765.93	14.30	-	-	-	-	14.30	780.23	9.40	853.57	73.34	-62.08	-
2007-08	853.57	38.31	2.25	-	-	-	40.56	894.13	9.09	975.41	81.28	-46.66	-
2008-09	975.41	53.97	-0.10	-	-	-	53.87	1,029.28	9.19	1,123.87	94.59	-33.88	-
2009-10	1,123.87	117.16	-	-	-	-	117.16	1,241.03	8.59	1,347.64	106.60	-55.92	-
2010-11	1,347.64	34.61	-	-	-	-	34.61	1,382.25	7.78	1,489.79	107.54	-38.15	-

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ
2011-12	1,489.79	26.94	9.50	-	-	-	36.44	1,526.23	7.80	1,645.27	119.05	-72.06	-
2012-13	1,645.27	45.76	5.00	-	-	-	50.76	1,696.03	8.08	1,833.07	137.04	-88.46	-
2013-14	1,833.07	67.49	2.54	-	-	-	70.03	1,903.10	7.71	2,049.83	146.73	-112.41	-
2014-15	2,049.83	44.93	-	-	-	-	44.93	2,094.76	7.91	2,260.46	165.70	-98.97	-
2015-16	2,260.46	43.27	14.54	-	-	-	57.81	2,318.27	7.95	2,502.57	184.30	-175.83	-
2016-17	2,502.57	48.04	10.07	-	-	-	58.11	2,560.68	7.60	2,755.29	194.61	23.85	0.87
2017-18	2,755.29	50.80	8.00	-	-	-	58.80	2,814.09	7.71	3,031.06	216.97	-84.08	-
2018-19	3,031.06	62.85	10.00	-	-	-	72.85	3,103.91	8.32	3,362.15	258.24	-100.71	-
2019-20	3,362.15	81.25	-	-	114.89	-	196.14	3,558.29	7.97	3,841.89	283.60	-154.41	-
योग:	1,145.89	63.95	-	-	114.89	-	1,324.73				2,517.17		

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी एवं नवीनतम अन्तिमिकृत लेखाओं के अनुसार

2019-20 की समाप्ति तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य 1999-2000 में ₹300.04 करोड़ से बढ़कर ₹3,841.89 करोड़ हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने ₹1,145.89 करोड़ इक्विटी के रूप में, ₹114.89 करोड़ परिचालन तथा प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान/सब्सिडी तथा ₹63.95 करोड़ ब्याज रहित ऋण के रूप में निवेश किया। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित निधियों की लागत की पूर्ति करने के कारण इन सभी वर्षों का कुल अर्जन ऋणात्मक या अपेक्षित न्यूनतम से कम ही रहा। 1999-2000 से 2019-2020 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों ने मात्र 2016-17 के दौरान लाभ अर्जित किया (₹23.85 करोड़) तथा इन्होंने शेष वित्तीय वर्षों में हानियां उठाई।

2.5.5 ऐतिहासिक लागत एवं निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश का प्रतिफल

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार ने ऐतिहासिक लागत⁴⁸ के आधार पर ₹1,324.73 करोड़ का निवेश किया था। धनात्मक प्रतिफल केवल 2016-17 में प्राप्त हुआ। 2016-17 में ऐतिहासिक लागत पर निवेश पर प्रतिफल 2.39 प्रतिशत था जबकि वर्तमान मूल्य पर यह 0.87 प्रतिशत था।

2.6 राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद होना

राज्य के 25 सार्वजनिक उद्यमों में तीन अकार्यशील कंपनियां थी जिनमें 31 मार्च 2020 तक ₹19.64 करोड़ (₹17.72 करोड़ एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड में एवं ₹0.92 करोड़ हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड और ₹1.00 करोड़ हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड) का कुल निवेश था, 31 मार्च 2020 की समाप्ति से विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या तालिका-2.15 में दी गई है।

⁴⁸ वर्ष के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत इक्विटी व परिचालन व प्रशासनिक व्यय हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा निवेशित कुल संचित निधियां हैं।

तालिका-2.15: राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	2	2	2	3	3

स्रोत: संबंधित वर्षों के हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) में सम्मिलित जानकारी

हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से परिसमापन प्रक्रियाधीन थी, जबकि हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश बेवेरेजेस लिमिटेड के सम्बन्ध में परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ की जानी हैं। राज्य सरकार राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करने के सम्बन्ध में उचित निर्णय लें।